प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल, प्रमुख सचिव,, उत्तरांचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी, नैनीताल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 19 मई,2004

विषयः श्री वीरेन्द्र सिंह राठौर पुत्र स्व०श्री चन्दन सिंह निवासी तल्लीताल नैनीताल को नगर पंचायत भीमताल के अन्तर्गत 40X15 फुट = 600 वर्ग फुट अर्थात 55.74 वर्ग मीटर भूमि को पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित व्यवसायिक कार्यो हेतु पट्टे पर आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—331/सात—एल0आर0सी0/2004 दिनांक 11 फरवरी,2004 के सन्दभ्र में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री विरेन्द्र सिंह राठौर पुत्र स्व० श्री चन्दन सिंह निवासी तल्ली ताल नैनीताल को पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित व्यवसायिक कार्य हेतु नगर पंचायत भीमताल की सीमा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम सागुड़ी गांव के गाटा संख्या—2061 व 1961 के अन्तर्गत रिक्त भूमि क्षेत्रफल 40X15 फुट = 600 वर्ग फुट अर्थात 55.74 वर्ग मीटर शासनादेश संख्या—258/16(1)/73—रा—1दिनांक9 मई, 1984 एंव शासनादेश संख्या—1695/97—1—1(60)/93—रा0—1 दिनांक 12 सितम्बर, 1997 में शिथलीकरण प्रदान करते हुए नजराना रू० 83,610—00 एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त अवशेष नजराना रू० 83,610—00 को 10 समान छ:माही किश्तों में भुगतान करने के उपरान्त तथा रू० 279—00 वार्षिक लगान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति की गयी है।

2— प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।

3— भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03(तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(2)

4— प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या—150/1/85(24)/रा—6 दिनांक 9 अक्टूबर,1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30—30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1, 1/2गुना से कम न होगा।

5— पट्टेदार एंव उसके उत्तराधिकारियों को आवंटित भूमि में वंशानुगत अधिकार होगा,

उत्तराधिकार पट्टेदार को लागू वैयक्तिक विधि द्वारा नियंत्रित होगा।

6— प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जाएगी तो भूमि निर्माण(structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।

7— यदि भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा यदि उसके मालिक का देहान्त बिना वारिस हो गया हो, तो भवन, स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो

जाएगी।

8— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या 01–07 तक में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि का निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- कृपया उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल) प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/

2 निदेशक, एन०आई०सी० उत्तरांचल।

3- श्री विरेन्द्र सिंह राठौर पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह निवासी 34 वर्डस तल्लीताल,नैनीताल।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सोहन लाल) अपर सचिव।